

निवेश बढ़ाने को भविष्य में होंगे और सुधार

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत को दिया भरोसा, कहा-निवेश का हॉटस्पॉट बन सकता है भारत

नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत को भरोसा देते हुए कहा कि भारत को वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए सुधारों का क्रम जारी रहेगा। उन्होंने सोमवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम में आर्थिक सुधारों को जारी रखने की बात कही।

सीआईआई के राष्ट्रीय एमएनसी कॉन्फ्रेंस 2020 में वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी की आपदा को भी अवसर में बदलने का काम किया है। हमारी सरकार ने दशकों से लटके आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया और उद्योग जगत के लिए नए अवसर मुहैया कराए। वित्तमंत्री ने भरोसा जताया कि सुधारों का क्रम आगे भी जारी रहेगा। कहा, भारत को वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। भविष्य में कुछ और बड़े सुधार किए जाएंगे, जिनका व्यापक असर दिखेगा। वित्तीय क्षेत्र का व्यावसायिक विकास किया जा रहा है, जो आर्थिक मजबूती की दिशा में बड़ा बदलाव साबित होगा। वित्तमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विनिवेश के एजेंडे को भी साथ लेकर चल रही है। इससे उत्पादकता तो बढ़ेगी ही बोझ बनी कंपनियों से पूंजी जुटाकर विकास कार्यों में लगाई जा सकेगी। रणनीतिक विनिवेश के जरिये हर साल होने वाले सरकार के खर्च पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। एजेंडा



74

अरब डॉलर
का प्रत्यक्ष
विदेशी निवेश
भारत आया
2019-20 में



अभूतपूर्व सुधारों से विकास के नए युग की शुरुआत : कांत

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कहना है कि सरकार ने शासन और आर्थिक मोर्चे पर अभूतपूर्व सुधारों से विकास के नए युग की शुरुआत की है। शोध और विकास को मजबूत करने के लिए और खर्च किए जाने की जरूरत है। सीआईआई के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम कारोबारी सुगमता पर तेजी से काम कर रहे हैं। इसे लेकर राज्यों की रैंकिंग भी शुरू की है। कोविड-19 की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था गिरावट की ओर जा रही है। ऐसे में कष्ट, श्रम और खनन क्षेत्र में व्यापक सुधार के जरिये रोजगार और विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है। श्रम सुधारों से भारत को विनिर्माण हब बनाने में मदद मिलेगी। 2019-20 भारत में 74 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया, जो 2013-14 में 36 अरब डॉलर था।

आयात पर निर्भरता घटने से इस साल चालू खाते में बचेंगे अरबों रुपये : सुब्रमणियन

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) केवी सुब्रमणियन ने कहा है कि कोविड-19 से प्रभावित वित्तवर्ष में भारत के चालू खाते में अरबों रुपये का सरप्लस रहेगा। सीआईआई के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत पर महामारी का दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अलग ही असर दिख रहा है। आयात और व्यापार घाटे में गिरावट की वजह से चालू खाते में सरप्लस रहेगा। इसके अलावा देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किए गए

सुधारों के कारण भी आयात पर निर्भरता घटी है। इसका असर चालू खाते पर दिख रहा है। रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों कहा था कि अप्रैल-जून तिमाही में देश के चालू खाते में रिकॉर्ड 19. अरब डॉलर का सरप्लस पहुंच गया है। पीएलआई जैसी योजना से भविष्य में विनिर्माण और उत्पादन बढ़ाने में और मदद मिलेगी।



विनिर्माण के लिए अवसर है पीएलआई योजना : मदरसन

ऑटो उपकरण निर्माता कंपनी मदरसन सूमी के चेयरमैन विवेक चांद सहगल ने सोमवार को कहा कि सरकार की ओर से शुरू की गई

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना विनिर्माण क्षेत्र के लिए अवसर है। इसका फायदा उठाकर कंपनी

2025 तक 36 अरब डॉलर के राजस्व का लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। योजना में ऑटो, फार्मा, टेलीकॉम, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, सोलर पीवी जैसे 10 क्षेत्रों के लिए 2 लाख करोड़ की पीएलआई योजना का एलान किया था।